



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 472]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 1983/कार्तिक 3, 1905

No. 472]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 1983/KARTIKA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह असंग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

अनुसूची

(आर्थिक कार्य विभाग)

(स्टाक एक्सचेंज प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1983

का० आ० 771(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार को मद्रास
स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड मद्रास की परिषद् की ओर से इस
आशय का एक लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ है, कि उसके
द्वारा बनाई गई उप-विधियों में संशोधन कर दिया जाए।

अतः अब प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,
1956 (1956 का 42) की धारा 10 की उप-धारा (i)
के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार
एतद्वारा मद्रास स्टాक एक्सचेंज लिमिटेड मद्रास की परिषद्
की उप-विधियों में, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट
संशोधन करती है और उस धारा की उपधारा (4) के
परन्तुक के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व्यापार के हित में
तथा विनिर्दिष्ट शेयरों के संबंध में किए गए संविदाओं के
अविलम्ब अनुपालन के लिए संविदा देने के निमित्त,
एतद्वारा, उप-विधियों में उक्त संशोधनों के पूर्व प्रकाशन
की प्रतीति से भी अभिमुक्ति प्रदान करती है।

मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड मद्रास की परिषद् की
उप-विधियों में :—

(1) उप-विधि 48 में, वर्तमान खण्ड (ii) के अन्त में
निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

“किन्तु यह व्यवस्था भी की गई है कि ऐसे शेयरों
के मामले में जिनको परिषद् द्वारा “विनिर्दिष्ट शेयर”
अभिहित किया गया है, सुपुर्दगी तथा अदायगी की
अवधियां शासी बोर्ड द्वारा प्रत्येक मामले में 14 दिन
और आगे तक इस तरह से बढ़ाई तथा स्थगित की
जा सकेंगी कि कुल मिला कर वह अवधि संविदा की
तारीख से 90 दिन से ज्यादा की न हो जाए।”

(2) उप-विधि “52” के बाद, एक नई उप-विधि
“52क” जोड़ दी जाएगी—

“विनिर्दिष्ट शेयरों में सौदे”

52क. जब तक परिषद् द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया
जाए “विनिर्दिष्ट शेयरों” में निम्नलिखित रीति से सौदे पूरे
किए जाएंगे।

(क) समस्त सौदों का निपटान हर 14 दिनों के बाद, जिसे इसमें इसके पश्चात् “निपटान अवधि” कहा गया है सुपुर्दगी तथा अदायगी के द्वारा अथवा उस रीति से किया जाएगा जिस का निर्धारण परिषद् द्वारा उपर्युक्त रीति के अतिरिक्त अथवा उस में संशोधन करते हुए किया जाए।

(ख) परिषद् प्रत्येक निपटान अवधि के संबंध में अग्रिम आधार पर प्रथम तथा अन्तिम व्यापार दिवस निश्चित करेगी।

(ग) सौदे हाजिर सुपुर्दगी अथवा दस्ती सुपुर्दगी अथवा विशेष सुपुर्दगी अथवा व्यवस्थापन के लिए किए जा सकेंगे किन्तु सौदा करते समय जब तक अन्यथा अनुबन्धित न किया जाए तब तक समस्त सौदों को तत्सामयिक व्यवस्थापन के लिए किए सौदे माना जाएगा।

(घ) निर्धारित व्यापारिक एकक अथवा उसके गुणितों से भिन्न एककों के सौदों का उप-विधि 48(ii) में यथा परिभाषित व्यवस्था के अनुसार दस्ती सुपुर्दगी के सौदों के रूप में माना जाएगा।

(ङ) जो सौदे चालू तथा अनुवर्ती निपटान अवधियों के आगे तक की अवधियों के लिए किए गए होंगे वे शून्य सौदे माने जाएंगे।

(च) एक निपटान अवधि से दूसरी निपटान अवधि में अग्रेणीत सौदे कार्यकारी निदेशक द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में सचिव द्वारा किसी भी प्रतिभूति के लिए निश्चित किए गए पूरक मूल्य पर किए गए सौदे माने जाएंगे।

(छ) निपटान अवधि के दौरान किए गए सौदों को क्रय अथवा विक्रय के द्वारा बन्धित किया जा सकेगा अथवा अगली निपटान अवधि में आगे तक ले जाया जा सकेगा। अन्य समस्त सौदे जो बकाया रहें उनको इस प्रयोजन के लिए निश्चित दिनों पर सुपुर्दगी तथा अदायगी द्वारा पूरा करना आवश्यक होगा।

(ज) इन उप-विधियों और विनियमों के समस्त उपबन्ध जो इस समय समाशोधित प्रतिभूतियों के सौदों के निपटारे पर लागू हैं और जो उपर्युक्त व्यवस्था के विरुद्ध नहीं हैं वे “विनिर्दिष्ट शेयरों” में सम्पन्न सौदों के निपटारे की व्यवस्था पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।”

(3) उप-विधि 72 के खण्ड (ग) के बाद एक नया खण्ड (घ) जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :—

“(घ) यदि परिषद् की राय में किसी प्रतिभूति में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट किस्म की कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो वह एक विशेष संकल्प के द्वारा विक्रेता द्वारा क्रेता को दिए जाने वाले विलम्ब छूट प्रभारों का विनियमन कर सकेगी।”

(4) उप-विधि 343 के खण्ड (1) में “एक्सचेंज का (आफ दी एक्सचेंज)” शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :—

“अथवा जिसमें दालेदार ने या तो स्वयं अदायगी न की हो, या किसी भी प्रतिभूति में सम्पन्न सौदों के संबंध में देय मार्जिन के अपवर्जन के मामले में व्यक्तिगत रूप से तालमेल जोड़ लिया हो।”

[एफ० संख्या 2/7/एस० ई०/83]

नीतीश सेनगुप्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 1983

S.O. 771(E).—Whereas the Central Government has received a request in writing from the Council of the Madras Stock Exchange Limited, Madras that the bye-laws made by it may be amended.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the amendments to the bye-laws of the Madras Stock Exchange Limited, Madras, specified in the Schedule below, and in pursuance of the proviso to sub-section (4) of that section the Central Government, in the interest of the trade, and to facilitate performance of contracts in respect of specified shares without delay hereby dispenses with the condition of previous publication of the said amendments to the bye-laws.

SCHEDULE

In the bye-laws of the Madras Stock Exchange Limited, Madras,—

(1) in Bye-law 48, at the end of the existing clause (ii) the following proviso shall be added, namely :—

“Provided however that in the case of such shares as may be designated by the Council as “specified shares”, delivery and payment may be extended or postponed by the Council by further periods of 14 days each, so that the overall period does not exceed 90 days from the date of the contract.”

- (2) after Bye-law 52, a new bye-law 52A shall be added, namely :—

“Bargains in specified share”.

52A. Unless otherwise determined by the Council, bargains in “specified shares” will be performed in the following manner :

- (a) All bargains shall be settled every fourteen days hereinafter called a “Settlement Period” by delivery and payment or as the Council may from time to time prescribe in addition thereto or in modification thereof.
- (b) The Council shall fix in advance the first and last business day for each settlement period.
- (c) The bargains may be for spot delivery or for hand delivery or for special delivery or for the settlement but unless otherwise stipulated when entering into the bargain, all bargains shall be deemed to be for the current settlement.
- (d) Bargains in other than the prescribed trading unit or multiples thereof shall be deemed to be for hand delivery as defined in Bye-law 48 (ii).
- (e) Bargains made for a period beyond the current and ensuing Settlement periods shall be void.
- (f) Bargains carried over from one settlement to another shall be at the making-up price fixed for any security by the Execu-

tive director or in his absence by the Secretary.

- (g) Bargains entered into during the settlement period may be closed by purchase or sale or carried over to the next settlement period. All other bargains which remain outstanding must be performed by delivery and payment on the days fixed for the purpose.
 - (h) All the provisions in these bye-laws and regulations which are at present applicable to the settlement of bargains in cleared securities and which are not in conflict with the above will apply mutatis mutandis to the settlement of bargains in “specified shares”.
- (3) after clause (c) of Bye-law 72, a new clause (d) shall be added, namely :—
- “(d) If in the opinion of the Council an emergency of the type referred to above has arisen in any security it may by a special resolution regulate the backwardation charges payable to the buyer by the seller”.
- (4) in clause (i) of Bye-law 343, after the words “of the Exchange”, the following words, shall be added, namely :—
- “or in which the claimant has either not paid himself or colluded with the defaulter in the evasion of margin payable on bargains in any security”.

[File No. F. 2/7/SE/83]
N. K. SENGUPTA, Jt. Secy.

